कौशल विकास

दिलीप कुमार

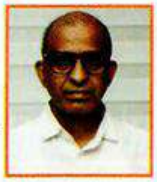

'पीएम-सेतु': कौशल विकास से विकसित भारत की मज़बूत नींव

जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ध्यान ऐसे संस्थानों के निर्माण पर केंद्रित हुआ है जो कुशल, संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित हों। 'पीएम-सेतु' शासन के इस बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो यह मानता है कि युवाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत उन संस्थानों को मज़बूत करने से होती है जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं।

सामान्य और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा भारत के शिक्षा और कार्यबल विकास इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) के एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में तेज़ी से उभर रहे हैं। हालांकि, उत्पादक व उद्योग-तैयार कार्यबल के निर्माण और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति को सुदृढ़ करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ऐतिहासिक रूप से तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया गया है। जैसे-जैसे भारत 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को हासिल करने की आकांक्षा रखता है, एक मज़बूत कौशल इकोसिस्टम का महत्त्व पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है।

कौशल विकास की बढ़ती राष्ट्रीय आवश्यकता

तकनीकी नवाचार, डिजिटलीकरण, ऑटोमेशन और उन्नत विनिर्माण द्वारा संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था के तीव्र बदलाव ने अत्यधिक कुशल कार्यबल की मांग को काफी बढ़ा दिया है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, रक्षा उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेश से आने वाले वर्षों में रोज़गार के महत्त्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि, इन निवेशों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रासंगिक तकनीकी दक्षताओं, व्यावहारिक कौशल और उद्योग के अनुकूल ज्ञान से लैस कार्यबल की उपलब्धता आवश्यक है। इसके साथ ही, कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं उम्रदराज आबादी और कार्यशील-आयु वर्ग में गिरावट का सामना कर रही हैं, जिससे कुशल मानव संसाधनों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। भारत, दुनिया की सबसे युवा आबादी और एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ, न केवल अपनी घरेलू कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल की आपूर्ति करके दुनिया की कौशल राजधानी के रूप में उभरने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।

लेखक, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय में महानिदेशक (प्रशिक्षण) हैं। ईमेलः dirgen-msde@gov.in

'पीएम-सेतु': संस्थागत परिवर्तन की नई पहल

इस संदर्भ में, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा और रोज़गार के बीच की खाई को पाटने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ये संस्थान न केवल व्यक्तियों को श्रम बाज़ार में तत्काल भागीदारी के लिए तैयार करते हैं, बल्कि बदलते उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर कौशल उन्नयन और रीस्किलिंग (पुनः कौशल विकास) का भी समर्थन करते हैं। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी, जो भारतीय युवाओं को घरेलू और वैश्विक दोनों श्रम बाज़ारों में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाए। इसलिए रोज़गार क्षमता बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि करने, नवाचार को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना आवश्यक है। एक मज़बूत कौशल विकास ढांचा भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की कमी को कम कर सकता है, वैश्विक कार्यबल गतिशीलता का समर्थन कर सकता है और लाखों युवाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान कर सकता है। नतीजतन, कौशल विकास में निवेश को केवल एक शैक्षिक प्राथमिकता के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए।

इस संदर्भ में, उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोज़गार क्षमता परिवर्तन ('पीएम-सेतु') योजना केवल एक और कौशल पहल नहीं है, बल्कि एक व्यापक संस्थागत सुधार है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और उनके अनुकूल बनाने का प्रयास करती है।

आईटीआई: कौशल विकास की रीढ़

दशकों से, आईटीआई भारत में व्यावसायिक शिक्षा की रीढ़ रहे हैं, जो युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र के अनुकूल नौकरियों के लिए तैयार करते हैं। इन संस्थानों ने जमीनी स्तर पर उद्योग-प्रासंगिक तकनीकी कौशल प्रदान करके कार्यबल के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

हालांकि, प्रौद्योगिकी और उत्पादन की बदलती प्रकृति ने मौजूदा व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर किया है। कई मामलों में पाठ्यक्रम तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे, कार्यशालाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और शैक्षणिक योजना में उद्योग की भागीदारी सीमित रही। नतीजतन प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने के बावजूद नियोक्ताओं को अक्सर कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए, यह चुनौती केवल उपकरणों को अपग्रेड करने या नए पाठ्यक्रम शुरू करने तक सीमित नहीं थी। इसके लिए स्वयं व्यावसायिक संस्थानों के शासन (गवर्नेंस) और कामकाज में बदलाव की आवश्यकता थी।

व्यापक सुधार की दिशा में 'पीएम-सेतु'

'पीएम-सेतु' (पीएम-एसईटीयू) भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में अब तक के सबसे महत्त्वाकांक्षी सुधारों में से एक के माध्यम से इस चुनौती का समाधान करता है। इस योजना के तहत 1,000 सरकारी आईटीआई के अपग्रेडेशन (नवीनीकरण) की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। इसके साथ ही, पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जाएगा।

पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग की भागीदारी वाले एक सहयोगात्मक जुड़ाव के रूप में तैयार किया गया है। हालांकि निवेश का यह पैमाना काफी बड़ा है, लेकिन 'पीएम-सेतु' की विशिष्ट विशेषता इसके शासन ढांचे (गवर्नेंस आर्किटेक्चर) में निहित है, जो संस्थागत प्रभावशीलता को इस सुधार के केंद्र में रखती है।

योजना की आवश्यकता को पहचानना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लंबे समय से भारत के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षित जनशक्ति की निरंतर आपूर्ति के साथ उद्योगों का समर्थन करते हैं। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है, बदलती उद्योग आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए आईटीआई इकोसिस्टम को मज़बूत और आधुनिक बनाने की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आईटीआई की संख्या और नामांकन दोनों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, लेकिन युवाओं के बीच उनके आकर्षण को बढ़ाने, उभरती प्रौद्योगिकी-संचालित पाठ्यक्रमों में भागीदारी का विस्तार करने, उद्योग के जुड़ाव में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के अवसर अब भी मौजूद हैं कि सीखने के परिणाम तेज़ी से बदलते कार्यबल की मांगों के अनुरूप हों। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता को मज़बूत करना, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रति अनुभव बढ़ाना और उद्योग के साथ साझेदारी को गहरा करना प्रशिक्षुओं को भविष्य के अनुकूल कौशल से लैस करने और एक गतिशील अर्थव्यवस्था में उनकी रोज़गार क्षमता में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

'पीएम-सेतु' की आवश्यकता आईटीआई को उद्योग के प्रति संवेदनशील उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में बदलने के दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई, जो आर्थिक विकास को गति दे सकें और सार्थक रोज़गार के अवसर पैदा कर सकें। यह योजना कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं का समाधान करती है, जिसमें बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, शासन और प्रशिक्षण प्रदान करने में उद्योग की अधिक भागीदारी, बेहतर शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) और कार्यस्थल पर सीखने (ऑन-द-जॉब लर्निंग) के अवसर, प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, बेहतर मूल्यांकन प्रणाली और मांग-संचालित व भविष्य-उन्मुख पाठ्यक्रमों की शुरुआत शामिल है। सरकार, उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देकर, 'पीएम-सेतु' का उद्देश्य एक अधिक आकांक्षी, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली बनाना है जो युवाओं की आकांक्षाओं का समर्थन करती है, उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करती है और भविष्य के लिए भारत के कुशल कार्यबल को मज़बूत करती है।

नई गवर्नेंस व्यवस्था की शुरुआत

'पीएम-सेतु' की प्रमुख विशेषताओं में से एक 'विशेष प्रयोजन वाहन' (स्पेशल पर्पस व्हीकल) के माध्यम से एक नए शासन (गवर्नेंस) मॉडल की शुरुआत करना है। इस तंत्र के तहत प्रत्येक हब आईटीआई तथा उससे संबद्ध स्पोक आईटीआई एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के अंतर्गत संचालित होंगे। इस एसपीवी में एक एंकर उद्योग भागीदार (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर) की बहुमत हिस्सेदारी होगी और वह दैनिक शैक्षणिक और परिचालन प्रबंधन (एकेडमिक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट) की जिम्मेदारी संभालेगा। केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक जवाबदेही की सुरक्षा के लिए स्वामित्व और निगरानी बनाए रखेंगी तथा निर्धारित आरक्षित विषयों पर नियंत्रण बनाए रखेंगी।

यह मॉडल संस्थागत दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उद्योग जगत को पाठ्यक्रम योजना, संकाय विकास और परिचालन संबंधी निर्णय लेने में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाकर, यह योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रम

बाज़ार की उभरती आवश्यकताओं के पूरी तरह अनुकूल रहे। यह 'हब-एंड-स्पोक' समूहों को स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में भी सक्षम बनाता है, जिससे क्षेत्र-विशिष्ट कौशल मांगों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्वामित्व समान पहुंच, पारदर्शिता और जवाबदेही के सामाजिक उद्देश्यों को बनाए रखता है।

सीखने के परिणामों पर विशेष बल

संस्थागत सुधार का अंतिम परिणाम सीखने के बेहतर नतीजों के रूप में सामने आना चाहिए और इसी के अनुसार 'पीएम-सेतु' पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण और रोज़गार क्षमता पर विशेष बल देता है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बिल्कुल अनुरूप है, जो व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने, उद्योग की प्रासंगिकता को मज़बूत करने और शिक्षा, कौशल विकास तथा रोज़गार के लिए लचीले और शिक्षार्थी-केंद्रित मार्ग प्रदान करने का प्रयास करती है।

हब आईटीआई से उद्योग की मांग के अनुसार लगभग चार नए ट्रेड शुरू करने और 10 मौजूदा ट्रेडों को अपग्रेड करने की उम्मीद है। इसी तरह, स्पोक आईटीआई भी नए ट्रेड शुरू करेंगे और अपने मौजूदा कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण करेंगे। प्रशिक्षण को राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे (नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क) के तहत तय किए गए मॉड्यूल-आधारित शिक्षण ब्लॉकों (मॉड्यूलर लर्निंग ब्लॉक्स) में व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे शिक्षार्थी क्रेडिट जमा कर सकेंगे और उच्च योग्यता व आजीवन सीखने (लाइफलॉन्ग लर्निंग) के लिए लचीले रास्तों को चुन सकेंगे।

यह योजना शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) के अवसरों, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग), प्लेसमेंट सहायता और करियर काउंसलिंग (परामर्श) को भी मज़बूत करती है, क्योंकि यह स्वीकार करती है कि सफल कौशल विकास केवल कक्षा के भीतर दी जाने वाली शिक्षा तक सीमित नहीं है। दीर्घकालिक रोज़गार के परिणामों का आकलन करने और निरंतर सुधार के लिए साक्ष्य (प्रमाण) जुटाने के उद्देश्य से 'स्नातक अनुवर्ती अध्ययन' (ग्रैजुएट ट्रेसर स्टडीज) भी आयोजित किए जाएंगे।

उद्योग भागीदारों के लिए लाभ

'पीएम-सेतु' योजना में भागीदारी उद्योग जगत को बदलते व्यावसायिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल व उद्योग-तैयार प्रतिभाओं की एक स्थायी पाइपलाइन प्रदान करके महत्त्वपूर्ण लाभ देती है। एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (प्रमुख उद्योग भागीदारों) के रूप में आईटीआई के शासन और कायाकल्प में सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से, उद्योगों को पाठ्यक्रम के डिजाइन, प्रशिक्षण मानकों, बुनियादी ढांचे के विकास और कौशल प्रदान करने की प्रक्रियाओं को आकार देने का अवसर मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षु वास्तविक दुनिया के संचालन से संबंधित दक्षताएं प्राप्त करें।

यह योजना उद्योगों को एक ऐसे कार्यबल तक पहुंच प्रदान करके भर्ती (रिक्रूटमेंट) और ऑनबोर्डिंग लागत को कम करने में भी सक्षम बनाती है जो क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित है और शिक्षुता तथा ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव से लैस है। इसके अलावा उद्योग की भागीदारी सरकार और कौशल विकास संस्थानों के साथ साझेदारी को मज़बूत करती है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के परिणामों को बेहतर बनाती है, उत्पादकता और नवाचार का समर्थन करती है तथा उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने में सक्षम भविष्य के अनुकूल कार्यबल के विकास में योगदान देती है।

नागरिक सशक्तीकरण का व्यापक दृष्टिकोण

नागरिक सशक्तीकरण के विषय को अक्सर रोज़गार या आय सृजन जैसे व्यक्तिगत परिणामों के संदर्भ में समझा जाता है। 'पीएम-सेतु' यह स्वीकार करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि स्थायी सशक्तीकरण समान रूप से सार्वजनिक संस्थानों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली जो उद्योग के प्रति उत्तरदायी है, शासन में जवाबदेह है और मापने योग्य परिणामों पर केंद्रित है, न केवल रोज़गार क्षमता को मज़बूत करती है बल्कि इन अवसरों को प्रदान करने वाले संस्थानों में जनता के विश्वास को भी बढ़ाती है।

सार्वजनिक निरीक्षण के साथ उद्योग की भागीदारी को एकीकृत करके, पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करके, जवाबदेही को मज़बूत करके और रोज़गार क्षमता को प्राथमिकता देकर, 'पीएम-सेतु' योजना आईटीआई को ऐसे गतिशील संस्थानों में बदलने का प्रयास करती है जो भारत के 'विकसित भारत' बनने की आकांक्षाओं का समर्थन करने में सक्षम हों।

संस्थागत सुधारों से विकसित भारत की ओर

जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ध्यान ऐसे संस्थानों के निर्माण पर केंद्रित हुआ है जो कुशल, उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित हों। 'पीएम-सेतु' शासन के इस बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो यह मानता है कि युवाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत उन संस्थानों को मज़बूत करने से होती है जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हालांकि यह योजना अभी कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में है, लेकिन यह एक ऐसे व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है जो एक आधुनिक, कुशल और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। ❑